एक 'खलनायक' की विदाई

शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के निधन पर 'संयम' के बावजूद शिवसैनिक तांडव करने से बाज नहीं आये

शिवसेना बाल ठाकरे ने 86 वर्ष की उम्र में अंतिम सांसें ली। वाइन, बीयर और बेहतरीन सिगारों के शौकीन वाला साहब ने 'फ्री प्रेस जनर्ल' से बतौर कार्टूनिस्ट अपने कॅरियर की शुरूआत की और बाद में कार्टून्स की मैगजीन का भी प्रकाशन किया।

बाल ठाकरे के कार्टून्स को देखने पर लगता है कि वास्तव में वे बेजोड़ प्रतिभा के धनी थे। अगर उन्होंने कार्टून बनाना छोड़ा नहीं होता तो आज देश ही नहीं, दुनिया के बेहतरीन कार्टूनिस्टों में शुमार होते।

लेकिन बाला साहब की राजनीतिक महत्त्वाकांक्ष ने उनके भीतर के व्यंग्यकार को मार डाला और उनकी रचनात्मक प्रतिभा एक खास दिशा में ही मुड़ गई जिसे ध्वंसात्मक अथवा विघटनकारी कहा जा सकता है।

महाराष्ट्र और खासकर, मुंबई की राजनीति में बाला साहब ने मराठाबाद और 'मराठी मानूष' का नारा देकर उन मराठी नवजवानों को अपने साथ जोड़ लिया जिन्हें मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे तेजी से आगे बढ़ते शहरों में नौकरियों एवं रोजगार के लिए अन्य प्रांतों से आये लोगों के साथ भीषण प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा था। मामले में वे कहीं अन्य प्रांतों से आये लोगों से पिछे न रह जाएं। ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि कॉस्मोपोलिटन कल्चर में प्रांतवाद, भाषणवाद, जातिवाद आदि पहचानों के लिए कोई जगह नहीं था। तेजी से आगे बढते इंडस्ट्रियल यूनिट्स, एंटरप्राइजेज और कॉरपोरेट्स को प्रतिभाशली, मेहनती और कार्यकुशल लोगों की ज़रूरत तथा और इस मामले में स्थानीय मराठी लोग खुद को कहीं न कहीं पीछे पा रहे थे, इसे लेकर उनमें भविष्य को लेकर जो असुरक्षा बोध पनप रहा था, उसे ताड़ने में बाला साहब ने जरा भी देर नहीं की और तत्काल 'मराठी मानूष' महाराष्ट्र में मराठियों के विशेषाधिकार का नारा देकर वे लोकप्रियता की सीढियां चढ़ने लगे। उनके द्वारा स्थापित शिवसेना जल्दी ही एक बड़ी ताकत के रूप में उभर गई। वीर शिवाजी के नाम पर स्थापित शिवसेना के मराठावाद और 'मराठी मानूष' के नारे के साथ कट्टर हिंदुत्ववाद की विचारधारा ने 'एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा' वाली कहावत को चरितार्थ किया और बाल ठाकरे ने सबसे पहले 'पुंगी बजाओ, लुंगी भगाओ' यानी मुंबई से दक्षिण भारतीय लोगों को आतंक के जोर पर भगाने का अभियान शुरू कर दिया। ढुलमुल कांग्रेसी राजनीतिक नेतृत्व ने इस विघटनकारी मराठावाद और खुनी गुंडागर्दी के सामने घुटने टेक दिये। बाला साहब को दक्षिण भारतीयों को मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों से खदेड़ने में कमोबेश सफलता मिली जिससे उनका हौसला और भी बुलंद हुआ।

ज़र्ललिज्म से कॅरियर की शुरूआत करने वाले बाला साहब को मीडिया की ताकत का भली-भांति अंदाजा था, इसलिए उन्होंने शिवसेना के मुख पत्र के रूप में 'सामना' का प्रकाशन शुरू किया और उसी के माध्यम से ज़हर उगलने का सिलसिला लगातार जारी रखा।

बाला साहब का यकीन लोकतंत्र में था, यद्यपि उनका संगठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हुआ, भाजपा के साथ गठबंधन कर महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज भी हुआ और अभी भी भाजपा के नेतृत्व में एनडीए के साथ है, यद्यपि ऐसा कई बार हुआ कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उग्र हिन्दूवादी तत्वों के लिए भी बाला साहब के अति उग्रहिंदूवादी विचारों को पचा पाना कठिन महसूस होने लगा। कुछ माह पहले की ही बात है, उन्होंने कहा था कि एक महिने के लिए भारतीय मिलीट्री की कमान उन्हें अगर सौंप दी जाये तो सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। समझा जा सकता है, उग्र हिंदू वाद, मराठावाद और सैन्यवाद। यानी ले-दे कर हिटलरवाद। बाला साहब का यकीन हिटलरवाद में था। लोकतंत्र में

नहीं। सैन्यवाद में था- वे राष्ट्र के सैन्यीकरण करना चाहते थे- सैन्यवाद के प्रति उनके आकर्षण को समझा जा सकता है- उन्होंने जो और वे सेना के स्वयंभू सुप्रीम कमांडर। ऐसे शख्स की यदि यह इच्छा हो कि उसे कम से कम एक माह के लिये भी भारतीय सेना की बगडोर सौंप दी जाये तो इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं।

बहरहाल, मुंबई से दक्षिण भारतीय लोगों को गुंडागर्दी के जोर पर भगा पाने में बाला साहब कमोबेश कामयाब रहे। इसके बाद उनकी घृणा की राजनीति का अगला शिकार उत्तर भारतीय बने। बिहार और यूपी से रोजगार की तलाश में मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहरों में गए लाखों-लाख लोग। अपने लंबे राजनीति कॉरियर के दौरान बाला साहब ने कई बार मुंबई से उत्तर भारतीयों को खदेड़ने की कोशिश की। बाला साहब ने शिवसैनिकों का एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो 'चौथ वसूली' से बाला साहब ने अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। चौथवसूली-उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, फिल्मी दुनिया से, टैक्सी-ऑटो चालकों से और रेहड़ी-पटरी वालों से भी। चौथ वसूली में मराठियों-गैर मराठियों में कोई भेदभाव नहीं बरता बाला साहब ने करोड़ों की वसूली, अरबों का साम्राज्य, घृणा की राजनीति, उग्र हिंदुत्ववाद की विचारधारा और हिंस्र भेड़ियावाद-इस सबसे बाला साहब को मुंबई का 'गॉडफादर' बना दिया। अक्खा मुंबई का अंडरवर्ल्ड माफिया एक तरफ और राजनीति के अंडरवर्ल्डके माफ़िया सरगना-यानी 'गॉडफादर' बाला साहब एक तरफ। अक्खा मुंबई उनके कदमों में सिर झुकाता था- क्या राजनीतिक नेता-सभी दलों के, क्या उद्योगपति- बॉम्बे डाइंग के नक्सली वाडिया से लेकर- अंबानी, फिर बड़े और छोटे अंबानी। फ़िल्म स्टार से राजनेता बने स्व. सुनील दत्त से लेकर बॉलीवुड के बिगबी अमिताभ बच्चन तक। सबके सिर बाला साहब के कदमों में झुके-'भयदान' के लिए। युसूफ खान यानी ट्रैजिडी किंग दिलीप कुमार साहब को 'निशान-ए-पाकिस्तान' अवार्ड मिला तो बाला साहब की भंवें टेढ़ी हो गईं। बाला साहब पाकिस्तान के नाम से कुछ उसी तरह भड़कते थे, जैसे लाल कपड़े से सांड। मुंबई में जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच खेलने आई, उनके इशारे पर शिवसैनिकों ने वानखेड़े स्टेडियम की पिच खोद डाली। बाला साहब पाकिस्तान और मुसलमान के खिलाफ थे और ताउम्र रहे। उनकी इच्छा थी कि भारत पाक को नेस्तनाबूद कर दे-अंजाम की परवाह उन्हें नहीं थी। वे जानते थे, जितना ज़हर वे उगलेंगे, जितनी घृणा फैलायेंगे, राजनीति में उतनी ही ज़्यादा कामयाबी उन्हें मिलेगी और कामयाबी उन्हें मिली, बेशक मिली। इसे भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य कहेंगे। हिटलर वंश का एक माफ़िया लीडर भारतीय लोकतंत्र में 'दूधों नहाया, पूतों फला।'

बाला साहब के सच्चे उत्तराधिकारी उनके भतीजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे हैं। बाला साहब ने यह स्वीकार किया था। पर पुत्रमोह से बड़ा मोह और कुछ नहीं होता। पुत्र मोह में उन्होंने उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे को सौंप दिया। राज ठाकरे अलहदा हो गए। पर उन्होंने बाला साहब से कम जलवे नहीं दिखाए। उत्तर भारतीयों यानी बिहार और यूपी के लोगों को मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे बड़े-बड़े शहरों से मार-मार कर भगाने में उन्होंने अद्भुत वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया है। उद्धव ठाकरे इस मामले में उनसे पिछे हैं।

बहरहाल, बाला साहब की शवयात्रा के दिन मुंबई के औचित्य पर एक भोली-भाली लड़की ने 'फेसबुक' पर एक कमेंट क्या कर दिया और उसकी एक सहेली ने उसे 'लाइक' क्या कर लिया, शिव सैनिकों ने कहर बरखा दिया। शिवसैनिकों की नाराजगी के बाद उस लड़की ने तुरंत 'फेसबुक' से अपना कमेंट हटा लिया, माफ़ी तक मांगी, अपना अकाउंट तक बंद कर दिया, पर पुलिस देर रात पूछताछ के लिए दोनों लड़कियों को थाना ले गई। दुसरे दिन उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया।

इस पर हंगामा हुआ। भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संविधानप्रदत्त अधिकार पर कुठाराघात बताया, केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया, टीवी चैनलों पर बहस चल पड़ी। लेकिन यह सब तो बाद में हुआ, इसके पहले ही शिवसैनिकों ने कमेंट करने वाली लड़की के डॉक्टर चाचा के नर्सिंग होम पर जमकर तांडव किया। तहस-नहस कर डाला नर्सिंग होम को। भर्ती मरीजों का भी ख्याल नहीं किया। बाला साहब को उनके समर्थक 'टाइगर' कहते थे। इस 'टाइगर' ने शिवसैनिकों के रूप में भेड़ियों को भर्ती की थी। सवाल है, टाइगर वाकई टाइगर था या भेड़ियों का सरदार? सवाल मौजूद है।

अब देखना है कि बाला साहब के नहीं रहने पर उनके 'उत्तराधिकारी' महाराष्ट्र की राजनीति में कौन-सा मुकाम हासिल करते हैं, जहां तक राष्ट्रीय राजनीति का सवाल है, यह तो वाला साहब ही अछी तरह समझ गए थे कि वहां उनकी कुछ खास औकात नहीं हो सकती । वह महाराष्ट्र और मराठावाद तक ही महदूद थे और रहना भी चाहते थे।

-मनोज कुमार झा

घरेलू महिला समिति का स्थापना सम्मेलन संपन्न

दिल्ली को कामगारों का शहर कहा जाता है देश के कोने-कोने से लोग यहां पर काम की तलाश में आते हैं। हालांकि वर्ष 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद से औद्योगिक इकाइयों को बड़ी संख्या में हटया गया परन्तु 1991 से लागू उदारीकरण की नीतियों के बाद बढ़ते सेवा क्षेत्र में अवसरों की कोई कमी न रही और देश की राजधानी दिल्ली में काम की तलाश में आने वालों का सिलसिला जारी रहा।

पूरे देश के अनुरूप दिल्ली में भी असंगठित क्षेत्र में कामगारों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। एक अनुमान के मुताबिक कुल कामगारों का 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में ही है। संगठित क्षेत्र जैसे बैंक, रेलवे इतयादि में भी ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मारुति जैसी कम्पनी में भी मज़दूर ठेके पर काम कर रहे हैं।

असंगठित क्षेत्रों में कामगारों की स्थिति बहुत विकट है। उसमें भी समाज में महिलाओं के प्रति जो रवैया है उसकी वजह से महिलाओं एवं बाल श्रमिकों की संख्या दोयम दर्जे की है, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम मज़दूरी प्राप्त होती है। महिलाओं की कमाई को सहायक कमाई के रूप में ही समझा जाता है। महिलाये भी संगठित तथा असंगठित क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में काम कर रही है, चाहे वह स्कूल कॉलेज हो या अस्पताल, फैक्टरी, मॉल या कॉल सेंटर। वह दिन की पाली से लेकर रात की पाली में भी काम कर रही है। लेकिन इन सभी में घरेलू कामगारों की स्थिति अधिक सोचनीय है, जिसका एक बड़ा कारण उनके काम के क्षेत्र में बिखराव है।

घरेलू कामगार महिलायें जो फ्लैटों व कोठियों में जाकर साफ-सफाई से लेकर बच्चों को रखने तक का काम करती है, उनके काम की कोई गारंटी नहीं है। जिसने जब चाहा रख लिया, जब चाहा निकाल दिया। फैक्टरी, स्कूलों तथा अन्य संस्थानों में काम करने वाली महिलायें एक छत के नीचे होती हैं तथा अपने सुख-दुख साझा करती है लेकिन घरेलू कामगारों के पास यह अवसर भी नहीं है। वह अलग-अलग घरों में काम करती है। किसी भी सरकारी मशीनरी का इनके बीच कोई दखल नहीं है। इन्हें फंड, बोनस, चिकित्सा सुविधायें

2 अक्टुबर 2012 को दिल्ली में 'घरेलू कामगार महिला समिति' का संविधान, घोषणा पत्र व मांगों को सदन में पारित कराया गया। समिति की कार्यकारिणी का चयन किया गया। जिसमें अध्यक्ष सीमा, उपाध्यक्ष सावित्री नेगी, सचिव ऋचा, सह-सचिव वीनू कोषाध्यक्ष स्नेहलता को चुना गया। कार्यकारी के सदस्यों का चुनाव 3 वर्ष के लिये किया गया। स्थापना सम्मेलन में 60-65 घरेलू कामगार महिलाओं ने शिरकत की।

प्राप्त नहीं है, न ही इनकी छुट्टियां निर्धारित हैं।

ऐसे अनेक मामले सामने आये हैं जहां नियोक्ता द्वारा महिला घरेलू कामगार का शारीरिक उत्पीड़न, बलात्कार किया गया लेकिन ऐसे मामलों से निपटने के लिए कोई प्रभावी कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाये गये। ये घरेलू कामगार महिलायें अमानवीय परिस्थितियों में काम करती हैं। कड़ाके की ठंड में नंगे पैर नियोक्ता के घर में काम करना होता है, उनका शौचालय इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती, बीमार पड़ने पर अपने बच्चों को भेज नियोक्ता के यहां काम करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त नियोक्ता के मन माफिक काम न होने पर उसके द्वारा हिंसा का शिकार भी बनती हैं। इनका वेतन इतना कम होता है कि उससे जीने की आवश्यक जरूरतों को भी पूरा नहीं किया जा सकता। जितनी कठिन परिस्थितियों में घरेलू कामगार महिलायें काम करती हैं। उससे कम चुनौतियां नहीं हैं, उन्हें संगठित करने में।

1.नई आर्थिक नीतियों के बाद सरकार ने जो अघोषित नीति बना रखी है उसकी वजह से नया ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड करवाना काफी कठिन हो गया है। इस ओर उठाये गये सभी प्रयासों को ऊंचे स्तर सही समाप्त करने की कोशिश की जाती है।

2. एक नियोक्ता न होने तथा कार्यक्षेत्र में बिखराव की वजह से ट्रेड यूनियन बनाना काफी कठिन है।

3. कामगार महिलाओं को सामने कोई ऐसा लक्ष्य दिखाई नहीं देता जिसे निशाना बना कर अपना विरोध प्रकट किया जा सके।

4. इस बात का भय कि यदि आवाज उठाई तो सीधे काम से निकाल दिया जायेगा।

ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में प्रगतिशील महिला एकता केन्द्र के कार्यकर्ताओं ने यह बीड़ा उठाया और-चार पांच सालों के प्रयासों के बाद घरेलू कामगार महिलाओं का स्थापना सममेलन किया गया।

इससे पूर्व रोहिणी के सैक्टर-26,सैक्टर-16 स्थिति कालोनी, शाहबाद डेरी, आजाद पूर में घरेलू कामगार महिलाओं के बीच संभवनायें लगातार चर्चा करके उनमें संगठित होने के लिये प्रेरणा पैदा की गई।

2 अक्टुबर 2012 को दिल्ली में 'घरेलू कामगार महिला समिति' का संविधान, घोषणा पत्र व मांगों को सदन में पारित कराया गया। समिति की कार्यकारिणी का चयन किया गया। जिसमें अध्यक्ष सीमा, उपाध्यक्ष सावित्री नेगी, सचिव ऋचा, सह-सचिव वीनू कोषाध्यक्ष स्नेहलता को चुना गया। कार्यकारी के सदस्यों का चुनाव 3 वर्ष के लिये किया गया। स्थापना सम्मेलन में 60-65 घरेलू कामगार महिलाओं ने शिरकत की।